भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2530

जिसका उत्तर 13.03.2025 को दिया जाना है

महाराष्ट्र में बाइपास सड़कें

2530. श्री संजय उत्तमराव देशमुख:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय राजमार्गों और राज्यीय राजमार्गों पर बाइपास के निर्माण के लिए सरकार द्वारा क्या प्रावधान किए गए हैं और मानदंड तय किए गए हैं;

(ख) महाराष्ट्र में विशेषकर वाशिम-यवतमाल निर्वाचन क्षेत्र में निर्मित राष्ट्रीय राजमार्गों और राज्यीय राजमार्गों की संख्या कितनी है तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का वाशिम-यवतमाल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में राज्यीय राजमार्ग-213 से राष्ट्रीय राजमार्ग-161 तक कोई बाइपास बनाने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो इसकी पूर्णता की समय-सीमा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) उक्त स्थानों पर ट्रैफिक जाम की स्थिति से निपटने और सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) बाईपास के निर्माण की आवश्यकता का आकलन विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करते समय गैर-शहरी यातायात, मार्गाधिकार (आरओडब्ल्यू) की उपलब्धता, शहरी/निर्मित खंडों में भीड़-भाड़, सड़क सुरक्षा संबंधी सोच-विचार आदि के लिए यातायात अपेक्षाओं के अनुसार, मामला-दर-मामला आधार पर किया जाता है और राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) कार्यों के अनुमोदित डीपीआर में तदनुसार प्रावधान किया जाता है।

(ख) बाईपास का निर्माण या तो एनएच उन्नयन कार्यों के हिस्से के रूप में या स्टैंडअलोन आधार पर किया जाता है। सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने महाराष्ट्र राज्य में विभिन्न एनएच पर 83 बाईपास का निर्माण किया है, जिसमें वाशिम-यवतमाल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एनएच-161 पर मेदशी, मालेगांव और वाशिम और एनएच-361 पर मडकोना, कलंब और यवतमाल नामक छह बाईपास शामिल हैं।

(ग) से (ङ) वाशिम-यवतमाल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के दिग्रस शहर में राज्यीय राजमार्ग-213 से एनएच-161 ए तक बाईपास के निर्माण के लिए ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। तथापि, सरकार ने वर्तमान यातायात जाम को कम करने और दिग्रस शहर से गुजरने वाले एनएच-161ए के खंड में सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 4-लेन बनाने को मंजूरी दे दी है, जिसके समापन की लक्षित तिथि मई, 2025 है।

*****